


उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)-7
संख्या: 87/xxvii(7)/2009
देहशून्य:दिनांक: 24मार्च,2009

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1710/xxx(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर,2007 के द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को भी उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें मंहगाई भत्ता सम्मिलित नहीं है, अनुमन्य किया गया है। कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13 नवम्बर,2007 के अनुसार प्रतिपूर्ति/मानदेय के बिल कोषागार को प्रस्तुत किये जाने पर कोषागार द्वारा आपत्ति लगाते हुए सम्बन्धित बिल वापस कर दिये गये हैं कि वेतन बैंड में देय मूल वेतन ही देय होगा उस पर देय ग्रेड वेतन को मूल वेतन में नहीं लिया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा वेतन समिति उत्तराखण्ड के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में यह उल्लिखित किया गया है कि संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" का तात्पर्य "उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा,परन्तु इसमें विशेष वेतन,वैयक्तिक वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।" प्रदेश के वाहन चालकों को 1 माह का वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने की व्यवस्था पूर्व से निर्गत शासनादेशों में है। अतः वाहन चालकों को मानदेय के भुगतान हेतु मूल वेतन का आशय उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 के अनुसार वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग से है। उक्त के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1-1-2006 से वित्तीय वर्ष 2008-09 में लागू किये गये हैं,वित्तीय वर्ष 2008-09 के उक्त वित्तीय वर्ष का मानदेय अभी नहीं दिया गया है, विगत वर्षों का मानदेय पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। अतः पूर्व वर्षों के लिये 01-वेतन की परिभाषा पूर्ववत् रहेगी जिसमें वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन के योग के अनुसार मानदेय दिया गया है, और उक्तवत् व्यवस्था वर्ष 2008-09 एवं अग्रतर जब तक यह व्यवस्था है तब तक ही लागू रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के फलस्वरूप वाहन चालकों को मानदेय के विषय में पूर्व में समय-समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: १३ (1)xxvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, भाजरा, देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
देवेन्द्र पालीवाल
(देवेन्द्र पालीवाल)
उप सचिव ।